

(ग) नगर भूमि अधिकतम सीमा पर नया कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धान और चावल की क्रय नीति

1983. श्री हीरा लाल शार० परमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान और चावल के क्रय की वर्तमान नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं जिसके अनुसार सरकार चावल मिलों की कुटाई के लिए धान की पूर्ति करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परिवर्तन का आधार क्या है और सरकार को होने वाले सम्भावित लाभ, इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित, क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) :

(क) धान और चावल की वसूली नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले की भांति, स्वैच्छिक पेशकश के आधार पर मूल्य समर्थन उपाय के रूप में धान की वसूली किसानों से बराबर सीधी की जा रही है, जबकि कुछेक राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई अनिवार्य लेवी के माध्यम से चावल के मिल मालिकों/व्यापारियों से चावल की वसूली की जाती है। मूल्य समर्थन योजना के अधीन मिलिंग प्रभारों का भुगतान कर चावल मिलों द्वारा बसूल की गई धान से चावल बनाया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

National Education Policy

1984. SHRI P. J. KURIEN: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state steps taken to evolve a national education policy for the country?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): A National Policy on Education was announced by a resolution by the Government of India in 1968.

Corrupt Practices in the Central Warehousing Corporation

1985. SHRI JAGPAL SINGH:

SHRI RAM VILAS PASWAN:

SHRI KUMBHA RAM ARYA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the press report appearing in the *Hindustan Times* dated 27th October, 1980 highlighting the corrupt practices in the Central Warehousing Corporation;

(b) if so, whether Government have made any inquiry into the working of the Corporation;

(c) if so, the result thereof; and

(d) the action taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The matter is being looked into.

Grants to Indian People's Theater Association

1986. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Indian People's Theatre Association (IPTA), Bombay has made any requests to the Department of Culture or Sangeet Natak Akademi for grants; and

(b) if so, when such request was made and what was the decision taken thereon?